1994 में हुए अपने खुले अधिवेशन में दिसम्बर, 1993 के संकल्प और कार्य-सम्हों द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन किया। अधिवेशन में अंगीकृत संकल्प, आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए, सभी संबंधित प्राधिकारियों को भेज दिए गए है।

तथापि, न्यायालयो में मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए कोई विनिर्दिष्ट नियम या विधि अधिकथित नहीं की गई है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ जांच

738. **श्री आस मोहम्मद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान महानिदेशक, जांच और पंजीकरण, द्वारा वर्ष-वार कितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ जांच की गई है और कितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही करने की सिफारिश की गई है, उनके मामले अभी भी एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग में लंबित है ;

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान लंबित और निपटाये गये मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बहुराष्ट्रीय कंपनियों के गलत कार्यकरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान महानिदेशक, जांच एवं पंजीकरण ने 14 मामलों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की सिफारिश की है। इनमें से 4 मामलों का पहले ही निपटान कर दिया गया है तथा शेष 10 मामले विभिन्न चरणों में विचाराधीन हैं या निर्णयाधीन हैं।

(घ) कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का संशोधन सरकार के विचाराधीन है ।

उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामले और रिक्तियां

739. **श्री अजीत जोगी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के उच्चतम न्यायालय की पूर्ण संविधान पीठ के समक्ष आज तक कुल कितने दीवानी और फौजदारी के मामले लम्बित हैं;

(ख) तीन वर्षों और पांच वर्षों से अधिक अवधि के कितने मामले लम्बित हैं ;

(ग) उच्चतम न्यायालय में इस समय न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त पड़े हैं और ये पद कब से रिक्त पड़े हुए हैं ;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने पद भरे गये हैं; और

(ङ) पुराने मामले शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क), (ख) और (ङ) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री से जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) 7-3-1995 को, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के 2 पद निम्नलिखित तारीखों से, रिक्त थे :—

1. 25-10-1994

2. 11-02-1995

(घ) पिछले तीन वर्षों (जनवरी, 1992 से मार्च, 1995 तक) के दौरान न्यायाधीशों के 13 रिक्त पद भरे गए ।